

विधि विभाग



मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम

1965

(क्रमांक 23 सन् 1965)

THE MADHYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM

1965

(No. 23 OF 1965)

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
1965

विधि विभाग



मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम
1965

(क्रमांक 23 सन् 1965)

THE MADHYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM
1965
(No. 23 OF 1965)

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
1995

MADHYA PRADESH ADHINIYAM

No. 23 of 1965

THE MADHYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1965

TABLE OF CONTENTS

Sections—

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

**CHAPTER II—ESTABLISHMENT OF THE BOARD OF SECONDARY EDUCATION, ITS
CONSTITUTION, FUNCTIONS, ETC.**

3. Incorporation of Board.
4. Constitution of Board.
5. Appointment of Chairman, term of office and conditions of his service.
6. Term of office and filling of casual vacancy, etc.
7. Quorum.
8. Powers of the Board.
- *[8-A. Disqualification for being member of the Board.]
9. Powers of the State Government.
10. Constitution of Board Fund.
11. Custody and investment of Board Fund.
12. Application of Board Fund.
13. Budget.
14. Audit and accounts of Board.
15. Powers and duties of Chairman.
16. Appointment, powers and duties of Vice-Chairman.

*. Section 8-A substituted by section 8 of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 23 वर्ष 1965

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965

विषय-सूची.

पहला अध्याय-प्रारम्भिक

बात—

1. अधिनियम नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.
2. परिभाषाएँ.

द्वितीय अध्याय-माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना, उसका गठन, उसके कर्तव्य, आदि

3. मंडल का नियम.
4. मंडल का गठन.
5. सभापति की नियुक्ति तथा उसकी पदावधि एवं सेवा शर्तें.
6. पदावधि और आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति, आदि.
7. मण्डल की शक्तियाँ.
8. मंडल की शक्तियाँ.
- *[8. क. मंडल का सदस्य होने के लिये निरर्हता.]
9. राज्य शासन की शक्तियाँ.
10. मंडल निधि का गठन.
11. मंडल निधि की अभिरक्षा और उसका विनिधान.
12. मंडल निधि का उपयोग.
13. मंडल.
14. मंडल के लेखाओं की लेखा-परीक्षा.
15. सभापति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य.
16. उपसभापति की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ और उसके कर्तव्य.

* बाप 8-क मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 वर्ष 1979 की बाप 8 द्वारा स्थापित की गई.

(ii)

Sections—

17. Officers and servants of Board.
18. Powers and duties of Secretary.
19. Executive Committee.

CHAPTER III—DIVISIONAL BOARD

- **20. [* * * * *]
- **21. [* * * * *]
- **22. [* * * * *]
- **23. [* * * * *]

*[23.-A. Termination of appointment of examiners, etc. for any remunerative work of the Board.]

CHAPTER IV—MISCELLANEOUS

24. Constitution of Committees, etc.
25. Exercise of powers delegated by Board to Committee, etc.
26. Proceedings not invalidate by reason of vacancies, etc.
27. Power to make rules.
28. Powers of Board to make Regulations.
- **29. [* * * * *]

CHAPTER V—REPEAL, ETC.

30. Repeal and Saving.
31. Transitory Provisions.
32. Powers to remove difficulty.

* Inserted by section 11 of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

** Omitted by Section 11 and 17 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994

41

बाधक-

17. मण्डल के महाधिकारी तथा सेवक.
18. सचिव की शक्तियां और कर्तव्य.
19. कार्यपालिका समिति.

तीसरा अध्याय-संभागीय मण्डल

- **20. [* * * * *]
- **21. [* * * * *]
- **22. [* * * * *]
- **23. [* * * * *]

*[23.क. परीक्षकों आदि की मण्डल के किसी पारिवर्तिका वाले कार्य के लिये की गई नियुक्ति की समर्पित.]

चौथा अध्याय-प्रकीर्ण

24. समितियों का गठन आदि.
25. मण्डल द्वारा समितियों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग आदि.
26. शक्तियों के कारण कार्यवाहियां अवधिपूर्वक नहीं होगी.
27. नियम बनाने की शक्ति.
28. विनियम बनाने की मण्डल की शक्तियां.
- **29. [* * * * *]

पांचवां अध्याय-निरसन आदि

30. निरसन तथा व्यावृत्ति.
31. अन्तर्गत उपबन्ध.
32. कठिनाई दूर करने की शक्ति.

* मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 स. 1989 की धारा 11 द्वारा अन्तः स्थापित की गई.

** मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 32 स. 1994 की धारा 11 एवं 17 द्वारा जोड़ा.

MADHYA PRADESH ADHINIYAM

No. 23 of 1965

THE MADHYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1965^{1,2}

[Received the assent of the Governor on the 29th September 1965, assent first published in the Madhya Pradesh Gazette, Extraordinary on the 30th September, 1965.]

An Act to provide for the establishment of a Board to regulate Secondary Education in Madhya Pradesh and other matters ancillary thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

³[(3) This section shall come into force at once and sections 2 to 32 shall come into force on such date as the State Government may, by ⁴ notification, appoint].

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Board" means the Board of Secondary Education established under section 3;

(b) "Bye-law" means a bye-law made under this Act;

⁵["(c) "Chairman" means the Chairman of the Board appointed under Section 5";]

⁵["(d) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under Section 19.]

⁵["(e) 'Other Backward Classes' means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F. 85/-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984.";]

1. For Statement of objects and reasons see Bill No. 68 of 1965 published in the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary, dated 11th September, 1965 (Hindi) pages 3288 to 3303 and the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary dated 11th September, 1965 (English) Pages 3304 to 3320.

2. For proceedings in Assembly see Madhya Pradesh Vidhan Sabha Proceedings dated 12-9-1965.

3. Substituted by section 2 of Madhya Pradesh Act (No. 3 of 1966).

4. Section 2 to 32 have been brought into force on the 10th day of November 1965 by Education Department Notification No. 12088-XK-2-65, dated the 10th November, 1965.

5. Substituted by Section 2 (I) and (II) of Madhya Pradesh Act (No. 31 of 1994).

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ वर्ष १९६५

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ १, २

[दिनांक २९ सितम्बर, १९६५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक ३० सितम्बर १९६५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का विनियमन करने के लिये मण्डल की स्थापना तथा उसके सहायक अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम.

भारत के गणराज्य के सोलहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :-

पहला अध्याय—प्रारम्भिक

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ कहलायेगा.

अधिनियम नाम, विस्तार
तथा प्रारम्भ.

(२) इसका विस्तार-क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा.

^३[(३) यह धारा तत्काल प्रवृत्त होगी तथा धारा २ से ३२ तक धारायें ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगी जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा नियत करे.]

२. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग में विरुद्ध न हो—

अर्थव्यवस्था.

(क) "मण्डल" से तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित माध्यमिक शिक्षा मण्डल से है;

(ख) "उपविधि" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधि से है;

^५(ग) "सभापति" से अभिप्रेत है धारा ५ के अधीन नियुक्त किए गए मण्डल के सभापति.]

^६(घ) "कार्यपालिका समिति" से अभिप्रेत है धारा १९ के अधीन गठित की गई कार्यपालिका समिति]

^५(ङ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. ८५/पञ्जीस-४-८४, दिनांक २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.]

उद्देश्य एवं कारणों के विवरण के लिए विधेयक क्रमांक ६८ वर्ष १९६५ देखिए जो मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक ११ सितम्बर, १९६५ में पृष्ठ ३३८८ से ३३०३ तक (द्वितीय में) और मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक ११ सितम्बर १९६५ में पृष्ठ ३३०४ से ३३२० तक (तृतीय में) प्रकाशित हुआ है.

विधान सभा के कार्य विवरण के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा कार्य विवरण दिनांक १२-९-१९६५ देखिए.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३ वर्ष १९६६ की धारा २ द्वारा स्थापित की गई.

धारायें २ से ३२ तक शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक १२०८८-बीस-सी-६५, दिनांक १०-१-१९६५ द्वारा १० नवम्बर, १९६५ से प्रवृत्त हुई.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३१, वर्ष १९९४ की धारा २ (I), (II) द्वारा प्रतिस्थापित की गई.

- (f) "Institution" means an institution imparting Secondary Education or an institution not admitted to the privileges of any University established by law and imparting training to the teachers for a certificate or a diploma course as the case may be, and includes a part of an institution;
- [(g) "Local bodies" means a Municipal Corporation constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), or a Gram Panchayat, Janpad Panchayat or Zila Panchayat, constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) as the case may be;]
- (h) "Managing Committee" means the managing committee constituted by the foundation society or the governing body, as the case may be, of a recognised institution;
- (i) "Middle School Education" means such education as the State Government may, by notification, define from time to time;
- (j) "recognised" with its grammatical variations used with reference to schools means recognised by the Board for the purpose of admission to the privileges of the Board;
- (k) "regulation" means a regulation made by the Board under this Act;
- [(l) "Secondary Education" means the education which follows immediately the stage of Middle School Education and precedes immediately the stage of education controlled by the Universities established by Law in India.];
- [(m) "Scheduled Caste" means a member of any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (n) "Scheduled Tribe" means a member of any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh, under article 342 of the Constitution of India.]

1. Substituted by Section 2 (iii), (iv) of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

2. Inserted by Section 2 of Madhya Pradesh Act No. 11 of 1979.

- (च) "संस्था" से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो माध्यमिक शिक्षा प्रदान करती हो या ऐसी संस्था से है जो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार न मिले हो और जो अध्यापकों को यथास्थिति प्रवाच-पत्र या उपाधि पत्र संबंधी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करती हो और उसमें संस्था का भाग सम्मिलित है;
- ¹[(ख) "स्थानीय निकायों" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित कोई नगरपालिका निगम, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या कोई नगर पंचायत, या मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत, अनपद पंचायत या जिला पंचायत।]
- (ज) "प्रबंध-समिति" से तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था की यथास्थिति प्रतिष्ठान संस्था (फाउन्डेशन सोसायटी) या सासी-निकाय द्वारा गठित प्रबंध समिति से है;
- (झ) "मिडिल स्कूल शिक्षा" से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है, जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर परिभाषित करे,
- (ञ) "शालाओं के सन्दर्भ में प्रयुक्त मान्यता-प्राप्त" से तात्पर्य, उसके व्याकरण सबंधी परिवर्तनों सहित, मंडल के विशेषाधिकार देने के प्रयोजन के लिये मण्डल द्वारा मान्यता-प्राप्त से है;
- (ट) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन मंडल द्वारा बनाये गये विनियम से है;
- ¹[(ठ) "माध्यमिक शिक्षा" से अभिप्रेत है ऐसी शिक्षा जो मिडिल स्कूल शिक्षा के प्रक्रम के ठीक पश्चात् आती हो और भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा नियंत्रित शिक्षा के प्रक्रम के ठीक पूर्व तक चलती हो।]
- ²[(ड) "अनुसूचित जाति" से तात्पर्य किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह के, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य से है।]
- (ड) "अनुसूचित जनजाति" से तात्पर्य किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर के समूह के जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य से है।

1- मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की धारा 2 (सीन) व (घाट) द्वारा प्रतिस्थापित।
2- मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 2 द्वारा अंगीकृत की गई।

- (i) three Principals/Head Masters of Institutions recognised by the Board of whom one shall be a woman;
- (ii) one Principal of Teachers Training Institutions or Training Colleges;
- (iii) six Teachers of Institutions recognised by the Board of whom at least one shall be a woman;
- (iv) three persons representing management including local bodies which run institution, recognised by the Board;
- (v) five members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly;
- (vi) two persons representing interest not represented otherwise :

Provided that out of twenty members nominated under clause (k) at least two members each shall be from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

- (2) the Name of every members shall be notified in the Madhya Pradesh Gazette."]

Appointment of
Chairman and
terms of office and
conditions of his
service.

5. (1) The Chairman shall be such person as may be appointed by the State Government, by notification, in this behalf.

(2) The term of office and other conditions of service of the Chairman shall be such as may be prescribed by rules.

Term of office and
fixing of casual
vacancy etc.

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| 6. ¹ [(1) | * | * | * | * | * |
| ¹ [(2) | * | * | * | * | * |
| ¹ [(3) | * | * | * | * | * |

²[(4) The term of office of the nominated members shall be three years from the date of the notification regarding nomination under sub-section (2) of Section 4 :

Provided that the term of members nominated under sub-clause (v) of clause (k) shall coterminus with the Legislative Assembly."]

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| ¹ [(5) | * | * | * | * | * |
|-------------------|---|---|---|---|---|

(6) If the State Government considers that the continuance in office of any nominated member is not in the public interest, the State Government may make an order terminating his nomination and thereupon he shall cease to be a member of the Board notwithstanding that the term for which he was nominated has not expired

1. Omitted by Section 4 of the Madhya Pradesh Act No. 31 of 1994.
2. Substituted by Section 4 of the Madhya Pradesh Act No. 31 of 1994

(एक) मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य/प्रधान अध्यापक जिनमें से एक महिला होगी;

(दो) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालयों का एक प्राचार्य.

(तीन) मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छः अध्यापक जिनमें से कम से कम एक महिला होगी;

(चार) स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबन्ध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं चलाते हों,

(पांच) मध्यप्रदेश विधान सभा के पांच सदस्य;

(छह) ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हुआ हो:

परन्तु खण्ड (ट) के अधीन नामनिर्दिष्ट बीस सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के कम से कम दो सदस्य होंगे.

(2) प्रत्येक सदस्य का नाम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.]

5. (1) सभापति ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य शासन द्वारा, इस संबंध में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किया जाय.

सभापति की नियुक्ति तथा उसकी पदावधि एवं सेवा शर्तें.

(2) सभापति की पदावधि तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो कि नियमों द्वारा विहित की जाय.

6.¹[(1) * * * * *]

पदावधि एवं कार्यकाल
रिक्त स्थानों की पूर्ति
करनी.

¹[(2) * * * * *]

¹[(3) * * * * *]

²[(4) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्देशन संबंधी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की होगी.

परन्तु खण्ड (ट) के उपखण्ड (पांच) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि विधान सभा के साथ-साथ समाप्त हो जाएगी."

¹[(5) * * * * *]

(6) यदि राज्य शासन का यह विचार हो कि किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य का अपने पद पर बना रहना लोकहित में नहीं है, तो राज्य शासन उसका नाम निर्वेशन समाप्त करने वाला आदेश दे सकेगा और तदुपरान्त वह इस बात के होते हुए भी कि वह अवधि जिसके लिये नामनिर्दिष्ट किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, मण्डल का सदस्य नहीं रहेगा.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 तन् 1994 की धारा 4 (चार) द्वारा जोड़.

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 तन् 1994 की धारा 4 (चार) द्वारा प्रतिस्थापित.

"(7) Any nominated member of the Board may resign his office by a letter addressed to the State Government and the same shall be notified in the official Gazette."

"(8) In the event of a casual vacancy occurring by reason of death, resignation or termination of nomination of a member or for any other reason, such vacancy shall be filled by nomination, and any person nominated to fill such vacancy shall hold office for the term for which it was tenable by the person in whose place he has been so nominated and no longer.";

(9) An outgoing member shall, if otherwise qualified, be eligible for re-election or re-nomination.

"(10) Where any nominated member absents himself, without prior permission of the Chairman from three consecutive meetings of the Board, he shall be deemed to have resigned from his office."

Quorum.

"7. The quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of members."

Powers of Board.

8. The Board shall have the following powers, namely :—

(a) to prescribe courses of instruction in such branches of Secondary Education as it may think fit;

"(aa) to make regulations for imposing penalties on candidates using unfair means in the examinations conducted by the Board;"

(b) to conduct examinations based on such courses and take all steps ancillary thereto;

(c) to admit to its examinations, on conditions that may be prescribed, candidates who have pursued the prescribed courses of instruction—

(i) in institutions recognised by the Board; or

(ii) privately;

"* * * * *

(d) to publish the results of its examinations;

1. Substituted by Section 4 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.
2. Substituted by Section 5 of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.
3. Substituted by Section 6 (i) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.
4. Profibus omitted by section 6 (u) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

¹“(7) मण्डल का कोई भी नामनिर्दिष्ट सदस्य राज्य शासन को संबोधित किये गए पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और उसे (पदत्याग को) राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.”]

¹“(8) किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या नामनिर्देशन की समाप्ति के कारण से या किसी अन्य कारण से होने वाली आकस्मिक रिक्ति की दशा में ऐसी रिक्ति नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी, तथा ऐसी रिक्ति के भरे जाने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति उतनी अवधि तक उस पद पर रहेगा, जितनी अवधि तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया है, उस पद पर रहता और उससे अधिक नहीं.”]

(9) बहिर्गामी सदस्य, यदि वह अन्यथा अर्ह हो, पुनर्निर्वाचन या पुनः नाम निर्देशन के लिये पात्र होगा।

¹“(10) जहां कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य सभापति की पूर्व अनुज्ञा के बिना मण्डल के तीन सम्मेलनों में लगातार स्वयं अनुपस्थित रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है।]

²[7. मंडल के किसी सम्मेलन के लिये गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी.]

8. मंडल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्,—

मंडल की शक्तियां

(क) माध्यमिक शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, शिक्षण पाठ्यक्रम विहित करना;

³[(कक) मंडल द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं में अनुचित साधन उपयोग में लाने वाले या परीक्षाओं में हस्तक्षेप करने वाले अभ्यर्थियों पर शास्तियां, अधिरोपित करने के लिये विनियम बनाना।]

(ख) ऐसे पाठ्यक्रमों पर आधारित परीक्षाओं का संचालन करना और उसके सहायक समस्त उपाय करना;

(ग) ऐसी अभ्यर्थियों को जिन्होंने—

(एक) मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में ; या

(दो) प्रायवेट तौर पर ;

शिक्षण के विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, ऐसी शर्तों पर, जैसी कि विहित की जाय परीक्षाओं में प्रवेश देना।

⁴[* * * * *]

(घ) अपनी परीक्षाओं के परीक्षा फल प्रकाशित करना।

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1974 की धारा 4 (चार) द्वारा प्रतिस्थापित.
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 5 द्वारा स्थापित की गई.
3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 6 (एक) द्वारा अन्तः स्थापित की गई.
4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 6 (दो) द्वारा परम्परा का शीर्ष किया गया.

- (e) to grant diplomas or certificates to persons who have passed the examinations of the Board;
- (f) to recognise institutions situated in Madhya Pradesh for the purposes of admitting them to the privileges of the Board.
- ¹[(ff) to prescribe conditions for recognition of schools or institutions including conditions of service of teachers, their qualifications, equipment, building and other educational facilities;
- (fff) to withdraw recognition from the institution, where the Board is satisfied after enquiry that its privileges are abused by it or that the conditions imposed by the Board for the recognition of such institution are not complied with :

Provided that de-recognition shall not ordinarily be made effective in the midst of an academic session :

Provided further that if any de-recognition is made effective in the midst of an academic session, the students of the school so de-recognised who would have been admitted in the Board's Examinations shall be allowed to appear privately.]

- (g) to call for reports from the ²[Commissioner of Public Instruction] on the condition of recognised institution or of institutions applying for recognition or to direct inspection of such institutions;
- (h) to adopt measures to promote physical, moral and social welfare of students in recognised institutions and to prescribe conditions of their residence and discipline;
- (i) to organise and provide lectures, demonstrations, educational exhibitions and to take such other measures as are necessary to promote the standard of secondary education;
- (j) to institute and award scholarships, medals and prizes under conditions that may be prescribed;
- (k) to demand and receive such fees as may be prescribed including fees for registration of teachers and Managing Committees applying for registration as such;
- ³[(l) to admit to its examination candidates who have pursued correspondence course conducted by the Board.

1. Inserted by Sections 6 (ix) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

2. For the words "Director Public Instruction" substituted by Section 5 (i) of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

3. Substituted by Section 5 (ii) of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

(क) मंडल की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

(ख) मध्यप्रदेश में स्थित संस्थाओं को मंडल के विशेषाधिकार देने के प्रयोजनों के लिये उनकी मान्यता प्रदान करना।

¹[(च) ज्ञाताओं या संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शर्तें, जिनके अन्तर्गत अध्यापकों की सेवा शर्तें, उनकी अर्हताओं संबंधी शर्तें, उपस्कर भवन, तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं संबंधी शर्तें भी आती हैं, विहित करना;

(चच) किसी संस्था की मान्यता को उस दशा में वापिस लेना जब कि जाच के पश्चात् मंडल का यह समाधान हो जाय कि उसके विशेषाधिकारों का उस संस्था द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, या यह कि ऐसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिये मंडल द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाना है।

परन्तु अमान्यता मामूली तौर से शैक्षणिक सत्र के मध्य में प्रवर्तित नहीं की जायेगी;

परन्तु यह और भी कि यदि अमान्यता शैक्षणिक सत्र के मध्य में प्रवर्तित की जाती है, तो इस प्रकार अमान्य की गई शाला के उन विद्यार्थियों को, जिन्हें कि मंडल की परीक्षाओं में प्रवेश दिया गया होता, परीक्षा में प्रायवेट तौर पर बैठने के लिये अनुज्ञात किया जायगा।]

(छ) मान्यता-प्राप्त संस्थाओं की या मान्यता के लिये आवेदन करने वाली संस्थाओं की दशा में के संबंध में ²[आयुक्त लोक शिक्षण] से रिपोर्ट सबब करना या ऐसी संस्थाओं के निरीक्षण का निदेश देना;

(ज) मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों के शारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिये उपाय ग्रहण करना और उनके निवास तथा अनुशासन की शर्तें विहित करना।

(झ) व्याख्यानों, प्रदर्शनी, शैक्षणिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना और उनकी व्यवस्था करना तथा ऐसे अन्य उपाय करना जोकि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये आवश्यक हों,

(ञ) ऐसी शर्तों के अधीन, जो कि विहित की जाए, छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(ट) ऐसी फीस की मांग करना, और प्राप्त करना, जोकि विहित की जाये, जिसमें राजस्वीकरण के लिये आवेदन करने वाले शिक्षकों तथा प्रबंध समितियों की राजस्वीकरण फीस भी सम्मिलित है;

³[(ठ) अपनी परीक्षाओं में उन अभ्यर्थियों को प्रवेश देना जिन्होंने मण्डल द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रमों का परिशीलन किया है।

1 मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 6 (तीन) द्वारा अन्तर्स्थापित

2 मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की धारा 5 (एक) द्वारा लोक संचालन लोक शिक्षण के स्तर पर स्थापित किया गया।

3 मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की धारा 5 (बी) द्वारा प्रतिस्थापित

(m) to advise the State Government as to the courses of instruction and syllabi of Middle School Education with a view to secure coordination between Middle School and Secondary Education;

¹[(mm) (i) to organise conference, seminars, symposiums to promote the standard of Secondary Education;

(ii) to organise workshops and training programmes for paper setters;

(iii) to take necessary steps with regard to modernising of school curriculum, strengthening of science and mathematics education, work experience and vocationalisation by making investigation and researches into the latest evaluation processes or other experiments;

(iv) to take all necessary steps to make examinations more valid, reliable, comprehensive and elaborate;

(v) to arrange for comprehensive evaluation of students through cumulative records and internal assessment records.]

(n) to do all other things ancillary to any of the purposes specified above or for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

qualification
of member
Board.

²[8-A. A person shall be disqualified for being nominated or for continuing as a member if he, directly or indirectly, by himself or by his partner :—

(a) has any share or interest in any publication prescribed as a text book of study for use in any institution imparting secondary education, or

(b) has any share or interest in any work done for or on behalf of the Board.

Explanation.—For the purpose of this section, the publication of a text book shall include its republication.]

of State
Government.

9. (1) The State Government shall have the right to address the Board with reference to anything conducted or done by the Board ³[* *] and to communicate to the Board its views on any matters with which the Board ³[* *] is concerned.

(2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has taken upon the communication, and shall furnish an explanation if it fails to take action.

1. Inserted by Section 6 (iv) of the Madhya Pradesh Act, No. 1 of 1979.

2. Substituted by Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

3. Omitted by Section 6 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

(ड) मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा में समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से मिडिल स्कूल शिक्षा के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण के संबंध में राज्य शासन को सलाह देना;

(इ) (एक) माध्यमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों, परिसंवादों का आयोजन करना;

(दो) प्रश्न पत्र बनाने वालों के लिये कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(तीन) नवीनतम-मूल्यांकन प्रक्रियाओं में अन्वेषण तथा गवेषणाये, करके या अन्य प्रयोग करके शालाओं की पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण करने, विज्ञान तथा गणित की शिक्षा, कार्य अनुभव तथा व्यवसायीकरण को सुदृढ़ आधार प्रदान करने, के संबंध में आवश्यक उपाय करना;

(चार) परीक्षाओं को अधिक विधिमान्य, विश्वसनीय, व्यापक तथा विस्तृत बनाने के लिये समस्त आवश्यक उपाय करना;

(पाच) आकलित (क्यूमुलेटिव) अभिलेखों तथा आंतरिक निर्धारण संबंधी अभिलेखों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन के लिये व्यवस्था करना;]

(ड) ऊपर उल्लिखित किये गये प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन से समनुषक्त या इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये अन्य समस्त कार्य करना;

३. कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाने या सदस्य के रूप में के लिये निरर्हित होगा, यदि वह स्वयं या अपने भागीदार द्वारा प्रत्यक्षतः या

अपना या अपना होने के लिये प्रयत्न करे।

किसी ऐसे प्रकाशन में, जो माध्यमिक शिक्षा देने वाली किसी संस्था में उपयोग में लाया जाने के लिये अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के रूप में विहित किया गया हो, कोई अश्लील या हित रखता हो;

किसी ऐसे कार्य में, जो मंडल के लिये या मंडल की ओर से किया गया हो, कोई अश्लील या हित रखता हो;

करण :- इस धारा के प्रयोजन के लिये किसी पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन के अन्तर्गत उसका पुनः प्रकाशन भी आयेगा।

राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह मंडल 3[* *] द्वारा संचालित की किसी ब्रांच के सदस्य में मंडल को संबोधित करे और किसी भी विषय पर जिससे का संबंध हो, अपने विचार संचालित करे।

राज्य शासन की अधिकार।

४. ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, जैसी कि वह उस सूचना पर करना कर चुका हो। राज्य शासन को रिपोर्ट देगा और यदि वह कार्यवाही न कर पाये देगा।

१ अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 6 (चार) द्वारा अन्तः स्थापित की गई।

२ अधिनियम क्रमांक सन् 1979 द्वारा स्थापित।

३ अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की धारा 6 द्वारा मोध.

(3) If the Board does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act as it may think fit, and the Board [* *] as the case may be, shall comply with such directions.

(4) When any emergency in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken, the State Government may exercise such of the powers of the Board [* *] under this Act, as it deems necessary without previous consultation with the Board [* *] and shall forthwith inform the Board of the action taken.

(5) The State Government may, by order in writing specifying the reasons thereof, suspend the execution of any resolution or order of the Board [* *] and prohibit the doing of an act ordered to be or purporting to be ordered to be done by the Board [* *] if the State Government is of the opinion that such resolution, order or act is in excess of the powers conferred by or under this Act upon the Board [* *].

[(6) * * * * *]

Constitution of
Board Fund

10. A Board Fund shall be formed for the Board, and all sums received by or on behalf of the Board under this Act or otherwise shall be placed to the credit thereof.

Control and
Investment of
Board Fund

11. All moneys at the credit of the Board Funds shall be kept in the Government treasury or at any Bank as the Board may with the approval of the Government determine:

Provided that nothing in this section shall be deemed to preclude the Board from investing such moneys as are not required for immediate expenditure in any of the Government securities.

Application of
Board Fund

12. Subject to the provisions of this Act, the Board Fund shall be applicable only to the payment of the charges and expenses incidental to the several matters specified in this Act and to any other purpose for which by or under this Act powers are conferred or duties imposed upon the Board [* *].

Budget

13. (1) The Board shall prepare in such manner as may be prescribed by regulations the budget for the ensuing financial year and forward it to the State Government for its sanction not later than the thirty-first day of January preceding such financial year. The State Government may pass such orders with reference thereto as it thinks fit and shall communicate the same to the Board by the 31st day of March preceding such financial year and the Board shall give effect to such orders.

Provided that if no sanction is communicated to the Board by the 31st day of March preceding the above, the budget shall be deemed to have been sanctioned by the State Government without any modification.

1. Omitted by Section 6 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

2. Omitted by Section 7 of the Madhya Pradesh Act, No. 32 of 1994.

(3) यदि मंडल युक्तियुक्त समझ के अतिरिक्त राज्य शासन के समाधान योग्य कार्यवाही न करे, तो राज्य शासन, मंडल द्वारा दिये गये किसी भी स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिनियम से संगत, ऐसे निदेश देगा, जिन्हें कि वह उचित समझे और यथास्थिति मंडल [1* *] ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

(4) यदि राज्य शासन की राय में किसी आपत्तिक स्थिति के कारण आप्र कार्यवाही करना अपेक्षित हो, तो राज्य शासन, मंडल [1* *] से पूर्व परामर्श किये बिना इस अधिनियम के अधीन, मंडल [1* *] की शक्तियों, में से ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जिसे कि वह उचित समझे और की गई कार्यवाही के संबंध में मंडल को तत्काल इतिहास देगा।

(5) राज्य शासन, मंडल [1* *] के किसी भी संकल्प या आदेश का निष्पादन, लिखित आदेश द्वारा, तत्संबंधी कार्यों का उत्प्रेषण करते हुये, निरूपित कर सकेगा, और ऐसे कार्य के किये जाने का प्रतिरोध कर सकेगा, जिसके कि किये जाने पर मंडल [1* *] द्वारा आदेश दिया गया हो या जिसके किये जाने का मंडल द्वारा आदेश दिया गया हो अभिप्रेत हो। यदि राज्य शासन की यह राय हो कि ऐसा संकल्प, आदेश या कार्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मंडल [1* *] की प्रदत्त शक्तियों की सीमा के बाहर है।

1(6)

10. मंडल के लिये एक मंडल-निधि गठित की जायेगी, और इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा मंडल द्वारा या मंडल की ओर से प्राप्त समस्त धनराशियां, उनके नामे जमा की जायेगी।

मंडल निधि का गठन

11. मंडल-निधि में जमा संपूर्ण धन शासकीय कोषागार में या किसी बैंक में जैसा कि मंडल, शासन के अनुमोदन से व्यवहारित करे, रखा जायेगा।

मंडल निधि की अधिकता और उचित विनियमन

परन्तु इस धारा में किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह मंडल को ऐसे धनों का, जो तत्काल व्यय के लिये अपेक्षित नहीं है, किन्हीं भी शासकीय प्रतिभूतियों में विनिधान करने से प्रतिवारित करती है।

मंडल निधि का उपयोग

12. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, मंडल-निधि का उपयोग इस अधिनियम में उल्लिखित किये गये अनेक मामलों के प्रसंग में होने वाले प्रचारों तथा व्ययों की देनगी के लिये और ऐसी किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये किया जायगा जिसके लिये कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मंडल [1* *] को शक्तियां प्रदान की गई हों या उस पर कर्तव्य अधिरोपित किये गये हों।

मंडल

13. (1) मंडल आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट ऐसी शक्ति में तैयार करेगा, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाय और उसे राज्य शासन की ओर उसकी मंजूरी के लिये ऐसे दिनांक को अर्पित करेगा जो ऐसे वित्तीय वर्ष के पूरा होने इकतीस जनवरी के पश्चात् का न हो। राज्य शासन उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जिन्हें कि वह उचित समझे और मंडल को ऐसे वित्तीय वर्ष के पूर्वगत 31 मार्च, तक उसका समूचना देगा और मंडल ऐसे आदेशों को प्रभावी बनायेगा।

परन्तु यदि मंडल की उपरिनिर्दिष्ट 31 मार्च तक मंजूरी की सूचना न दी जाय तो बजट के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह बिना किसी रूप में मंडल के राज्य शासन द्वारा मंजूर कर लिया गया है।

1 मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 वर्ष 1994 की धारा 6 द्वारा जोड़ा
2 मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 वर्ष 1994 की धारा 7 द्वारा जोड़ा

(2) The Board may, if it considers it necessary so to do, prepare a supplementary budget during any financial year for such year and submit it to the State Government for its sanction not later than the thirty first day of October in the said financial year. The State Government may pass such orders with reference thereto as it thinks fit and shall communicate the same to the Board by the 30th day of November of the said financial year and the Board shall give effect to such orders :

Provided that if no sanction is communicated to the Board by the 30th November, the supplementary budget shall be deemed to have been sanctioned by the State Government without any modification.

Audit of accounts
of Board.

14. The accounts of the Board '[* *] shall be audited annually by such agency as may be specified by the State Government and a copy of the audited accounts and balance sheet shall be submitted by the Board to the State Government by such date each year as the State Government may, by rules, specify.

Powers and duties
of Chairman.

15. (1) It shall be the duty of the Chairman to see that this Act and the regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(2) The Chairman may, whenever he thinks fit, call a meeting after giving a notice of not less than twentyone clear days and shall be bound to do so, within fourteen days of the receipt of a written requisition signed by not less than ²[fifteen members] of the Board and stating therein the business to be brought before the meeting.

(3) In any emergency, arising out of the business of the Board which, in the opinion of the Chairman requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary, and shall thereafter report his action to the Board at its next meeting.

(4) The Chairman shall exercise such other powers as may be vested in him by regulations.

³[(5) The Chairman may delegate such powers and entrust such duties as are conferred or imposed on him by or under this Act to the Secretary by an order in writing specifying the powers delegated.]

Appointment,
powers and duties
of Vice-Chairman.

16. (1) The State Government may in consultation with the Chairman appoint any person to be a Vice-Chairman of the Board.

(2) The term of the office and other conditions of service of the Vice-Chairman shall be such as may be prescribed by rules.

(3) The Vice-Chairman shall assist the Chairman in all matters administrative or academic and shall exercise such powers and perform such functions of the Chairman as may be delegated or entrusted to him by the Chairman.

1. Omitted by Section 8 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

2. For the words "twenty members" substituted by Section 9 (i) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of the 1979.

3. Inserted by Section 9 (ii) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

(2) मंडल, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे वर्ष के लिये अनुपूरक बजट तैयार करेगा और उसे राज्य शासन की उसकी मंजूरी के लिये ऐसे दिनांक को प्रस्तुत करेगा जो उक्त वित्तीय वर्ष के इक्कीस अक्टूबर के पश्चात् का न हो, राज्य शासन उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जिन्हें कि वह उचित समझे और मंडल को उक्त वित्तीय वर्ष के तीस नवम्बर तक उसकी संसूचना देगा और मंडल ऐसे आदेशों की प्रभावी बनायेगा।

परन्तु यदि मंडल को तीस नवम्बर तक मंजूरी की संसूचना न दी जाये, तो अनुपूरक बजट के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह बिना किसी रूप में देन के राज्य शासन द्वारा मंजूर कर दिया गया है।

14. मण्डल ¹[* *] के लेखाओं की लेखा-परीक्षा प्रतिवर्ष ऐसे अभिकरण द्वारा की जायेगी जो कि राज्य शासन द्वारा उल्लिखित किया जाये और लेखा-परीक्षित लेख और सन्तुलन-पत्र (बैलेन्स शीट) की एक प्रति मंडल द्वारा राज्य शासन को प्रति वर्ष ऐसे दिनांक तक प्रस्तुत की जायेगी जिसे कि राज्य शासन नियमों द्वारा उल्लिखित करे।

मंडल के लेखाओं की लेखा-परीक्षा

15. (1) सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम का और विनियमों का पालन निष्ठापूर्वक किया जा रहा है और उसे इस प्रयोजन के लिये आवश्यक समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

सभापति की शक्तियां तथा कर्तव्य

(2) सभापति, जब कभी वह उचित समझे, कम से कम पूरे 21 दिन की सूचना देने के पश्चात् सम्मेलन बुला सकेगा और ऐसी लिखित अध्याचना के, जो कि मण्डल के कम से कम ²[पंद्रह सदस्यों] द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें सम्मेलन के समक्ष लाये जाने वाले कामकाज का उल्लेख हो, प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर, ऐसा करने के लिये बाध्य होगा।

(3) मंडल के कामकाज से उत्पन्न होने वाली किसी आपत्तिक स्थिति में, जो कि सभापति की राय में यह अपेक्षा करती हो कि तत्काल कार्यवाही की जाये, सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् मंडल को उसके आगामी सम्मेलन में, अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट देगा।

(4) सभापति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा उसमें निहित की जाय।

³[(5) सभापति एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कि प्रत्यायोजित की गई शक्तियां उल्लिखित की गई हों, सचिव को ऐसी शक्तियां जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सभापति को प्रदत्त की गई हों, प्रत्यायोजित कर सकेगा तथा ऐसे कर्तव्य, जो कि इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन सभापति पर अधिरोपित किये गये हों, सौंप सकेगा।]

16. (1) राज्य शासन सभापति के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को मंडल का उपसभापति नियुक्त कर सकेगा।

उपसभापति की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और कर्तव्य

(2) उपसभापति की पदावधि तथा अन्य सेवा-शर्तें ऐसी होंगी जो कि नियमों द्वारा विहित की जाय।

(3) उपसभापति समस्त प्रशासनिक अथवा शैक्षणिक मामलों में सभापति की सहायता करेगा और सभापति की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि सभापति द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाय तथा सभापति के ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि सभापति द्वारा उसे सौंपे जाय।

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1974 की धारा 8 (ख) द्वारा सौंप।

2. शब्द "बीस" सदस्यों के स्थान पर मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 9 (एक) द्वारा स्थापित किये गये।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 9 (दो) द्वारा अन्तः स्थापित की गई।

Officers and servants of Board.

17. (1) There shall be a Secretary and such number of Deputy Secretaries to the Board as the State Government may consider necessary.

(2) Appointment of the Secretary and the Deputy Secretaries shall rest with the State Government.

[(3) The Board may, subject to the provisions of sub-section (5), appoint such officers including Assistant Secretaries and servants as it considers necessary for the efficient performance of its functions.]

(4) The qualifications, the conditions of appointment and service and the scales of pay of officers and servants of the Board shall—

(a) as respects the Secretary, and the Deputy Secretaries be such as may be specified by rules made by the State Government; and

(b) as respects Assistant Secretaries, other officers and servants as may be determined by regulations made under this Act.

[(5) The Board shall not create a post save with the prior approval of the State Government.]

Powers and duties of Secretary.

18. (1) The Secretary shall be the principal administrative officer and shall, subject to the control of the Chairman, perform such duties as may be assigned to him by the Board.

(2) The Secretary shall be responsible for seeing that all moneys are expended on the purposes for which they are granted or allotted.

(3) The Secretary shall be responsible for keeping the minutes of the Board.

(4) The Secretary shall be entitled to be present and to speak at any meeting of the Board and the Executive Committee but shall not be entitled to vote thereat.

(5) The Secretary shall exercise such other powers as may be laid down in regulations.

Executive Committee.

19. (1) There shall be constituted an Executive Committee consisting of the members of the Board as follows :—

(a) The Chairman;

(b) The Commissioner, Public Instruction;

(c) The Commissioner, Tribal Development;

(d) Member representing the Finance Department;

1. Substituted by Section 10 (i) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

2. Substituted by Section 9 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

3. Substituted by Section 10 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

17. (1) मंडल का एक सचिव होगा, तथा उतने उप-सचिव होंगे जितने कि राज्य सासन आवश्यक समझे।

मंडल के सचिवों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होगी।

(2) सचिव तथा उपसचिवों की नियुक्ति राज्य शासन पर निर्भर होगी।

¹[(3) मंडल, उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे पदाधिकारियों को, जिनके अंतर्गत सहायक सचिव तथा सेवक आते हैं, नियुक्त कर सकेगा जिन्हें कि वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक समझे।]

(4) मंडल के पदाधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा की शर्तें तथा वेतनमान—

(क) सचिव तथा उपसचिवों के संबंध में ऐसे होंगे, जैसे कि राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा उल्लिखित किये जायें; और

(ख) सहायक सचिवों, अन्य पदाधिकारियों तथा सेवकों के संबंध में ऐसे होंगे जैसे कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

²[(5) मण्डल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कोई पद सृजित नहीं करेगा;"]

18. (1) सचिव, प्रधान प्रशासकीय पदाधिकारी होगा और सभापति के नियंत्रण के अधीन रहते हुये, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे कि उसे मंडल द्वारा सौंपे जायें।

सचिव की नियुक्ति और कार्य

(2) सचिव, इस बात को देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि संपूर्ण धन उन्हीं प्रयोजनों पर व्यय किया जाता है जिनके लिये वह मंजूर किया गया है या बटित किया गया है।

(3) सचिव, मंडल का कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) सचिव, मंडल तथा कार्यपालिका समिति के किसी भी सम्मेलन में उपस्थित रहने का और बोलने का हकदार होगा किन्तु उसमें मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयोग में लायेगा जो विनियमों में निर्धारित की गई हों।

³[19. (1) मण्डल में सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यपालिका समिति निम्नलिखित रूप में गठित की जाएगी :—

कार्यपालिका समिति

(क) सभापति;

(ख) आयुक्त, लोक शिक्षण;

(ग) आयुक्त, शहरी जाति विकास;

(घ) वित्त विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 10 (एक) द्वारा स्थापित की गई।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की धारा 9 द्वारा स्थापित।

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की धारा 10 (घ) द्वारा नहीं धारा का स्थापन।

(c) Member representing School Education Department.

(f) Five members to be nominated by the Board from amongst the members nominated under sub clauses (i) to (vi) of clause (k) of sub-section (1) of Section 4 whom two shall be from amongst members nominated under clause (v).

(2) The Chairman and Secretary of the Board shall act as Chairman and Secretary of the Executive Committee.

(3) The Executive Committee shall meet at least once in three months :

Provided that the Chairman may call the meeting at any time if he deems necessary.

(4) Five members shall form the quorum for the meeting of the Executive Committee.

(5) Subject to the general control, direction and superintendence of the Board, the Executive Committee shall be competent to deal with any matter within the competence of the Board.".]

CHAPTER III—DIVISIONAL BOARD

Divisional Board.

| | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|
| 20. | 1* | * | * | * | * |
| 21. | 1* | * | * | * | * |
| 22. | 1* | * | * | * | * |
| 23. | 1* | * | * | * | * |

Termination of appointment of examiners, etc., for any remunerative work of the Board.

[23-A. (1) If at any time it appears to the Board that the person appointed for any remunerative work of the Board, has been guilty of any misconduct or negligence which renders the appointment for a particular work inexpedient the Board may make an order terminating his appointment and directing that such person shall not be eligible for appointment for the particular work at any time or for any specific period. Before making such order, the Board shall observe such procedure as may be prescribed.

(2) The name of the person against whom an order has been made under sub-section (1) shall not be included in the panels of names of such period as may be specified in such order.]

1. Omitted by Section 11 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.
2. Inserted by Section 11 of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

(द) स्कूल शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;

(च) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्ड (एक) से (छह) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से मण्डल द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पांच सदस्य, जिनमें से दो उपखण्ड (पांच) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से होगा।

(2) मण्डल का सभापति तथा सचिव, कार्यपालिका समिति के क्रमशः सभापति तथा सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(3) कार्यपालिका समिति तीन मास में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगी :

परन्तु सभापति यदि आवश्यक समझे तो किसी भी समय सम्मिलन बुला सकेगा।

(4) कार्यपालिका समिति के सम्मिलन की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

(5) कार्यपालिका समिति, मण्डल के सामान्य नियंत्रण निदेश और अधीक्षण के अधीन, मण्डल सक्षमता के भीतर किसी भी मामले में कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी।

तीसरा अध्याय—संसाधनीय मण्डल

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|----------------|
| 20. | 1* | * | * | * | * | संसाधनीय मण्डल |
| 21. | 1* | * | * | * | * | |
| 22. | 1* | * | * | * | * | |
| 23. | 1* | * | * | * | * | |

23-क. (1) यदि किसी भी समय मण्डल को यह प्रतीत हो कि मंडल के किसी पारिश्रमिक वाले कार्य के लिये नियुक्त किया गया व्यक्ति किसी ऐसे अवचार या किसी ऐसी उपेक्षा का दोषी रहा है कि जिससे किसी विशिष्ट कार्य के लिये वह नियुक्त असमीचीन हो जाती है, तो मंडल उसकी नियुक्ति को समाप्त करते हुए तथा यह निर्दिष्ट करते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी समय उस विशिष्ट कार्य के लिये या किसी उल्लिखित कालावधि तक के लिये नियुक्त किये जाने हेतु पात्र नहीं होगा, एक आदेश कर सकेगा, ऐसा आदेश करने के पूर्व, मंडल, ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित की जाय।

किसी व्यक्ति को किसी पारिश्रमिक वाले कार्य के लिये नियुक्त करने के लिये

(2) उस व्यक्ति का, जिसके कि विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया हो नाम, नामों के पेनल में ऐसी कालावधि तक के लिये सम्मिलित नहीं किया जायगा जो कि ऐसे आदेश में उल्लिखित हो।

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की धारा 11 द्वारा जोड़ दिया गया।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 11 द्वारा अन्तः स्थापित की गई।

CHAPTER IV—MISCELLANEOUS

Constitution of
Committees etc.

¹[24. "(1) The Board may from amongst its members and officers and other persons constitute such committees as may be prescribed by Regulation, to aid and advise the Board and the Executive Committee in discharge of their functions and in particular may constitute the following committees :—

- (1) Curriculum Committee;
- (2) Committees of Courses;
- (3) Examination Committee;
- (4) Finance Committee;
- (5) Recognition Committee."

¹["(2) Every such committee shall consist of such members of the Board and of such other persons as may be prescribed by the regulations ".]

²[(3) * * * * *]

(4) Members of such Committees ³[* * * *] shall hold office during such time as the Board which appointed them specifies from time to time ;

Provided that if the term of the Board appointing such Committees expires before the term so specified the Committees shall hold office till new Committees are appointed by the Successor Board.

⁴[(5) * * * * *]

Exercise of powers
delegated by
Board to Commit-
tees, etc.

25. All matters relating to the exercise by the Board of powers conferred upon it by this Act which have, by regulations been delegated by the Board ⁵[* * *] to any ⁶[* * *] Committee constituted under section 24 shall stand referred to that Committee, and the Board before exercising any such powers shall receive and consider the report of the Committee with respect to the matter in question.

Provided that where in the opinion of the Board immediate action is necessary with respect to any such matter, it may proceed to deal with it without the report of the Committee in respect thereof and pass such orders thereon as it considers necessary.

¹ Sub-section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1974.
² Chapter 12 of Section 12 of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.
³ Which are the co-opted members of the Board by section 12 (ii) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.
⁴ Which are the co-opted members of the Board by section 12 (ii) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.
⁵ Chapter 12 of Section 12 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1974.

गठित
की ज
समिति

1.
विनियमों

2[(

(4)
मंडल, जि

परन्तु
की गई
समितियों

4[(5)

25.
प्रयोग है
गठित की
यदि समिति
के सम्बन्ध

परन्तु
आवश्यक हो
के लिए अज्ञा

1 नमूना
2 मध्य
3 मध्य
4 मध्य
5 मध्य

बीजा अध्याय-प्रकीर्ण

¹[24] (1) मण्डल, अपने सदस्यों, और अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों में से ऐसी समिति गठित कर सकेगा जैसी कि मण्डल को सहायता और सलाह देने के लिए विनियमों द्वारा विहित की जाए और कार्यपालिका समिति उसके कृत्यों के निष्पादन में और विशिष्टितया निम्नलिखित समितियाँ गठित कर सकेगा :-

समितियों का गठन
आदि

- (1) पाठ्यचर्या समिति;
- (2) पाठ्यक्रम समिति;
- (3) परीक्षा समिति;
- (4) वित्त समिति;
- (5) मान्यता समिति²।

¹[(2) प्रत्येक ऐसी समिति में मण्डल के ऐसे सदस्य होंगे तथा ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएँ,]

²[(3) * * * * *]

(4) ³[* * *] ऐसी समितियों के सदस्य, ऐसे समय के लिये पद धारण करेंगे, जिसे कि मण्डल, जिसने उन्हें नियुक्त किया है, समय-समय पर उल्लिखित करे :

परन्तु यदि ऐसी समितियों को नियुक्त करने वाले मण्डल की अवधि इस प्रकार उल्लिखित की गई अवधि के पूर्व ही समाप्त हो जाये तो समितियाँ, उत्तराधिकारी मण्डल द्वारा नयी समितियों की नियुक्ति की जाने तक पद धारण किये रहेगी।

⁴[(5) * * * * *]

25. मण्डल द्वारा ऐसी शक्तियों के, जो इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदान की गयी हो, प्रयोग से संबंधित समस्त मामलों, जो कि मण्डल ने विनियमों द्वारा ⁵[* * *] धारा 24 के अधीन गठित की गयी किसी ⁶[* * *] समिति की प्रत्याबोधित कर दिये हैं, उस समिति को निर्दिष्ट किये गये समझे जायेंगे, और मण्डल किन्हीं भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के पूर्व प्रस्तावित विषय के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

मण्डल द्वारा समितियों
को प्रत्याबोधित की
गयी शक्तियों का प्रयोग,
आदि

परन्तु जहाँ मण्डल की राय में किसी भी ऐसे मामले के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो वहाँ वह उसके सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट के बिना ही उस पर कार्यवाही करने के लिए अग्रसर हो सकेगा, और उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

1. मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 अगस्त 1944 की धारा 12 द्वारा प्रति स्थापित।
2. मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 12 अगस्त 1971 की धारा 12 (एक) द्वारा सुपुर्ण की गई।
3. मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 अगस्त 1979 की धारा 12 (बी) द्वारा सुपुर्ण किये गये।
4. मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 अगस्त 1979 की धारा 12 (डीन) द्वारा सुपुर्ण की गई।
5. मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 अगस्त 1944 की धारा 13 द्वारा शक्तियों का ज्ञापन किया गया।

Proceedings not
invalidate by reason
of vacancies.

26. Subject to the provisions of this Act or any rules, regulations or byelaws made thereunder, no act or proceeding of the Board, ¹[* *] the Executive Committee or of a Committee constituted under section 24 shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy amongst the members of the Board; ¹[* *] or such Committee.

Power to make
rules.

27. (1) The State Government may, ¹[* *] make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) All rules made under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power of Board to
make regulations.

28. ²[(1) The Board may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.]

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may make regulations providing for all or any of the following matters, namely—

¹[(a) * * * * *]

(b) the constitution, powers and duties of Committees constituted under section 24;

³[(bb) the imposition of penalty on candidates using unfair means or interfering the the examination conducted by the Board;]

(c) The award of diplomas or certificates;

⁴[(d) the conditions of recognition of institutions for purposes of admission to the privileges of the Board, the qualification and condition of service of teachers and framing of a School Code to ensure a minimum standard of efficient and uniform management of such institutions;]

(e) the courses of study to be laid down for all diplomas or certificates;

(f) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for diplomas or certificates.;

(g) the fees for admission to the examination of the Board;

(h) the conduct of examinations;

(i) the appointment of examiners and their duties and powers in relation to the Board's Examinations;

1. Omitted by Section 14, 15, 16, of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

2. Substituted by Section 13 (a) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

3. Inserted by Section 13 (b) (i) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

4. Substituted by Section 13 (b) (ii) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

26. इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों के अधीन रहते हुए, मण्डल ¹[* *] कार्यपालिका समिति का या धारा 24 के अधीन गठित की गयी किसी समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अवधिपूर्वक नहीं होगी कि मण्डल, ¹[* *] या ऐसी समिति के सदस्यों में कोई रिक्ति विद्यमान थी।

रिक्तियों के कारण कार्यवाही अवधिपूर्वक नहीं होगी।

27. (1) राज्य शासन, ¹[* *] इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

28. ²[(1) मंडल इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों।]

नियम बनाने की शक्ति की सविशेषता।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डल निम्न लिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध करते हुए विनियम बना सकेगा, अर्थात् :-

¹[(क) * * * * *]

(ख) धारा 24 के अधीन गठित समितियों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य;

³[(खख) मंडल द्वारा संचालित की गई परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग में लाने वाले या परीक्षा में हस्तक्षेप करने वाले अभ्यर्थियों पर शास्ति का अधिरोपित किया जाना;]

(ग) उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों का प्रदान किया जाना;

⁴[(घ) मण्डल के विशेषाधिकार देने के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शर्तें अध्यापकों की अर्हता संबंधी शर्तें और उनकी सेवा-शर्तें तथा ऐसी संस्थाओं के दक्षतापूर्ण एवं एक से प्रबंध का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के हेतु शाला-सहिता (स्कूल कोड) का बनाया जाना।]

(ङ) समस्त उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों के लिए निर्धारित किया जाने वाला पाठ्यक्रम;

(च) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थियों को मण्डल की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायगा और वे उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों के लिये पात्र होंगे;

(छ) मण्डल की परीक्षा में प्रवेश के लिये फीस;

(ज) परीक्षाओं का संचालन;

(झ) परीक्षकों की नियुक्ति और मण्डल की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य तथा शक्तियाँ;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 33 सन् 1994 की धारा 14, 15, 16 द्वारा शर्तों का जोष किया गया।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 13 (क) द्वारा स्थापित की गई।
3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 13 (ख) (एक) द्वारा अन्तःस्थापित की गई।
4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की धारा 13 (ख) (बी) द्वारा स्थापित की गई।

- (j) the admission of institutions to the privileges of recognition and the withdrawal of recognition;
- (k) the appointment of officers, clerks and others servants of the Board and the conditions of their service;
- (l) the constitution of Provident Fund for the benefit of the officers, clerks and other servants employed by the Board.
- (m) the control, administration, safe custody and management in all respects of the finances of the Board; and
- (n) all matters which by this Act are to be or may be provided for by regulations.

(3) The regulations made under this section shall be subject to the condition of previous publication in the manner set forth in section 24 of the Madhya Pradesh General Clauses Act, 1957 (3 of 1958), and shall not take effect until they have been sanctioned by the State Government and published in the Gazette.

(4) When the final draft of the regulations is submitted by the Board to the State Government for sanction under sub-section (3), the State Government shall within a period of three months from the date of submission of such draft communicate to the Board either its sanction or refusal to the draft or may suggest such modifications therein as may be deemed necessary in the draft. If the State Government fails to take any action, the final draft as submitted by the Board shall be deemed to have been sanctioned by the State Government and shall be published in the Gazette accordingly.

[(29) * * * * *]

CHAPTER V—REPEAL, ETC.

30. (1) As from the date specified for the establishment of the Board under sub-section (1) of Section 3, the following consequences shall ensue, namely :—

- (a) the Madhya Pradesh Secondary Education Act, 1959 (10 of 1959), shall stand repealed;
- (b) the Board of Secondary Education existing immediately before the date aforesaid shall cease to exist;
- (c) all assets and liabilities of the Board referred to in clause (b) shall vest in the Board established under Section 3;

1. Omitted by Section 17 of the Madhya Pradesh Act No. 31 of 1994.

- (अ) संस्थाओं को मान्यता के विवेकाधिकारों का दिया जाना और मान्यता का वापिस लिया जाना;
- (ट) मण्डल के पदाधिकारियों, लिपिकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति और उनकी सेवा-शर्तें;
- (ठ) मण्डल द्वारा नियोजित पदाधिकारियों, लिपिकों तथा अन्य सेवकों के फायदे के लिये भविष्य-निधि का गठन;
- (ड) मण्डल के वित्तों का समस्त रूपेण नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षित-अभिरक्षा तथा प्रबन्ध; और
- (ढ) ऐसे समस्त विषय जो इस अधिनियम द्वारा, विनियमों द्वारा उपबोधित किये जाने हों या किये जा सकें.

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये विनियम मध्यप्रदेश जर्नल क्लार्क एक्ट, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 24 में उल्लिखित की गयी रीति में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे और तब तक प्रकाशनी नहीं होंगे जब तक कि वे राज्य शासन द्वारा मंजूर न कर लिये जाय और राजपत्र में प्रकाशित न कर दिये जाय.

(4) जब विनियमों का अंतिम प्रारूप, मण्डल द्वारा राज्य शासन को उपधारा (3) के अधीन मंजूरी के लिये प्रस्तुत किया जाय, तो राज्य शासन ऐसे प्रारूप के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से तीन मास की कारावाही के भीतर मण्डल को या तो प्रारूप के मंजूर कर लिये जाने या अस्वीकार कर दिये जाने के सम्बन्ध में सूचित करेगा या उसमें ऐसे रूपभेदों का सुझाव देगा जो कि प्रारूप में आवांशक समझे जाय यदि राज्य शासन कोई कार्यवाही न करे, तो मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतिम प्रारूप राज्य शासन द्वारा मंजूर किया हुआ समझा जायगा और तदनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया जायगा.

1(29) * * * * *

पाँचवा अध्याय—निरस्तन आदि

30. (1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन मण्डल की स्थापना के लिये उल्लिखित किये गये दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे -

- (क) मध्यप्रदेश संकेपडरी एज्युकेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 10 जून, सन् 1959) निरस्त हो जायगा;
- (ख) पूर्वोक्त दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान 21 ग्रामिक शिक्षा मण्डल, अस्तित्व में नहीं रहेगा;
- (ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये मण्डल की समस्त आस्तियाँ तथा दायित्व धारा 3 के अधीन स्थापित किये गये मण्डल में निर्दिष्ट हो जायेगी;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की धारा 17 द्वारा शीप किया गया.

- (d) all employees belonging to or under the control of the Board referred to in clause (b) immediately the employees of the Board established under Section 3;

Provided that the terms and conditions of service of such employees shall not, until altered by a competent authority, be less favourable than those admissible to them while in service of the Board referred to in clause (b);

- (e) all records and papers belonging to the Board referred to in clause (b) shall vest in and be transferred to the Board established under Section 3.

(2) Notwithstanding the repeal of the Madhya Pradesh Secondary Education Act, 1959 (10 of 1959), things done or omitted to be done and action taken by any authority by or under the provision of the said Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under this Act.

Transitory
Provisions.

31. Notwithstanding anything contained in this Act, the Executive Committee constituted under Act repealed under Section 30 shall continue to function till such time as the Executive Committee is constituted in accordance with the provisions of Section 19.

Power to remove
difficulty.

32. If any doubt or difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provisions, not inconsistent with the purposes of this Act, as appear to them to be necessary or expedient for removing the doubt or difficulty.

(घ) पूर्वोक्त विनाक के ठीक पूर्व, खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये मण्डल के या उसके नियंत्रणाधीन समस्त कर्मचारी धारा 3 के अधीन स्थापित किये गये मण्डल के कर्मचारी समझे जायेंगे,

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें, जब तक वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित न की जाय, उन निबन्धनों तथा शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये मण्डल की सेवा में रहते हुये उनके लिये स्वीकार्य थी,

(ङ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये मण्डल के समस्त अभिलेख तथा कागद धारा 3 के अधीन स्थापित किये गये मण्डल में निहित हो जायेंगे तथा उसकी अन्तर्गत हो जायेंगे.

(2) मध्यप्रदेश सेकन्द्री एज्युकेशन एक्ट, 1959 (क्रमांक 10 सन् 1959) के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के उपबन्ध द्वारा या उसके अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा की गई या करने से छोड़ दी गई बातें तथा की गई कार्यवाही, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जावेगी

31. इस अधिनियम में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, धारा 30 के अधीन निरसित अधिनियम के अधीन गठित कार्यपालिका समिति ऐसे समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार कार्यपालिका समिति गठित न हो जाय.

32. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य शासन, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो कि उसे शंका या कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो.